मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

सत्ता हथियाने को खर्चे गये 100–100 करोड़ रुपए
नाकारा हैं सेक्टर 8 का अस्पताल व 11 डिस्पेंसरियां 3

'नमक का दरोगा'
विनाशकारी व्यवस्था का विकास पुरुष 4

यौन हिंसा और पूंजीवाद के भ्रामक नारे
मां के दूध का व्यवसाय 6

लोकसभा चुनाव : मज़दूरों की समस्याए किसी घोषणापत्र में नहीं 8

वर्ष 27 अंक 11 फरीदाबाद, बुधवार, 16-30 अप्रैल 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

हुड्डा की उल्टी गिनती शुरू

कहने को हुड्डा की सरकार के पास अभी सितम्बर तक का वक्त है पर हरियाणा की जनता के पास उन्हें देने के लिये सिवाय धक्के के और कुछ नहीं। कुशासन, भ्रष्टाचार और महंगाई ने जो हाल सारे देश में कांग्रेस का किया है वही हरियाणा में भी होता दीख रहा है। साथ ही, राज्य में 'आप' का प्रादुर्भाव 'प्रापर्टी डीलर' हुड्डा को व्यक्तिगत रूप से नंगा करके छोड़ेगा।

फ़रीदाबाद, मज़दूर मोर्चा बयूरो

10 अप्रैल को हरियाणा में लोकसभा मतदान ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक किस्मत पर सत्ता-निर्वासन की अन्तिम मुहर लगा दी है। रोहतक संसदीय सीट छोड़ कर और कुछ हद तक भिवानी, कुरूक्षेत्र, गुड़गांव में मुकाबले के दिखाबे में शामिल होने के अलावा, 16 मई को

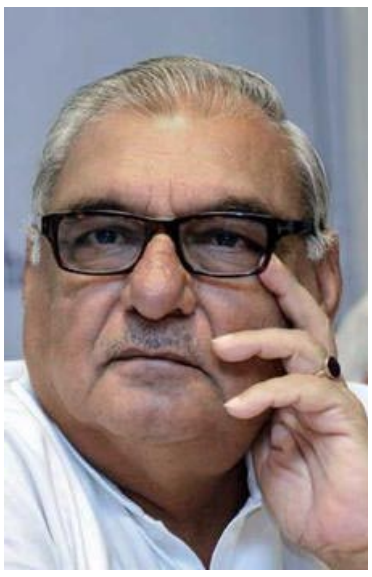

आने वाले चुनाव परिणाम कांग्रेस को हरियाणा में ठिकाने लगानेवाले ही सिद्ध होंगे।

स्वयं हुड्डा के लिये राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने का एक लम्बा दौड़ शुरू होने जा रहा है। इस बार उन्हें हाईकमांड नहीं हटायेगी-दरअसल हाईकमांड तो उन्हें विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रखना ही चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस में ले-देकर हुड्डा के चेले-चांटे ही कुछ न कुछ स्थानीय प्रभाव क्षेत्र बना सके हैं। इस बार हुड्डा को हरियाणा की जनता हटाने जा रही है और जब नौबत यह आ जाये तो इसकी कोई काट होती नहीं।

हुड्डा की किस्मत से हरियाणा में कोई हरीश रावत नहीं है। उत्तराखंड में बदनाम विजय बहुगुणा को हटाना था तो हरीश रावत का दावा काम आ गया।

हरियाणा के दावेदारों में न किसी की वैसी साख बची है और न ही उनमें वैसा दम नज़र आता है। हुड्डा के पार्टी के भीतर समानांतर दावेदारों में जब-तब 4 नाम उछलते रहे है-वीरेन्द्र सिंह, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला। वीरेन्द्र सिंह को कांग्रेसी हल्कों में भी सजावटी महत्व का ही माना जाता है, न कि पार्टी को मुसीबत के समय में कोई चमत्कारी नेतृत्व दे सकनेवाला। कुमारी शैलजा तो लोकसभा चुनाव छोड़कर ही भाग खड़ी हुईं। चलो हाईकमांड से नजदीकी के चलते उन्हें राज्यसभा की शरणस्थली मिल गयी। किरण चौधरी में संघर्ष के तेवर जरूर थे पर एक तो अब समय नहीं रहा और दूसरे हुड्डा खेमा कभी भी उनके नाम पर तैयार नहीं होगा। रहे रणदीप सुरजेवाला जो अपेक्षाकृत युवा भी हैं। और हुड्डा व राहुल दोनों के विश्वासपात्र भी कहे जा सकते हैं। पर उनका राजनीतिक कद ऐसा नहीं कि पूरी तरह डूबी हुई पार्टी की नैया को मझधार से निकाल सकें।

राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा भी गरम है कि केन्द्र में आनेवाली नयी सरकार हुड्डा को महज एक हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी मानकर बख्श देगी या छटा हुआ अपराधी सिद्ध करना चाहेगी। यह बहुत कुछ आगामी विधानसभा चुनाव की प्रचार की पिच पर निर्भर करेगा। यहां, हुड्डा की बदकिस्मती से, 'आप' की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 'आप' का हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार काफ़ी हद तक हुड्डा के भ्रष्टाचार पर केन्द्रित होने जा रहा है। वे, हुड्डा की प्रॉपर्टी डीलर वाली छवि को लगातार उछालना चाहेंगे। इसी एक तीर से अनेकों शिकार होते हैं। हुड्डा सरकार को जनविरोधी, किसान विरोधी, पूंजीशाहों की गोद में बैठने वाली युवाओं को बेरोजगार करने वाली मंहगाई बढाने वाली, नौकरियां बेचने वाली, भ्रष्ट प्रशासन देने वाली, बताया जा सकता है।

ऐसे में भाजपा भी पीछे क्यों रहेगी? उसे भी यदि माहौल को अपने लिए भुनाना है तो 'आप' की तर्ज पर, बल्कि उससे बढ-चढ कर, हुड्डा परिवार एवं सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। यदि कहीं केन्द्र में उनकी सरकार बन गयी तो मुद्दा उठाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसे परिणति तक पहुंचाने के लिये आपराधिक मुकदमे दर्ज करने होंगे, जांचे बैठानी पड़ेगी और नौबत गिरफ़्तारी तक भी आ सकती है। औम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमन्त्रियों के लिये जेल यात्रा की मिसाल कायम कर ही दी है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस क्रम में अगले मुख्यमंत्री सिद्ध हो तो आश्चर्य नहीं। हुड्डा को यह मरोड़ तो रहेगी कि 'नम्बर वन हरियाणा' का नारा प्रचार माध्यमों में तो चर्चित रहा पर हरियाणा की जनता के गले नहीं उतरा। उतरता भी कैसे जब कदम-कदम पर कुशासन और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और शासन की हर नीति का एक ही मकसद हो-प्रॉपर्टी डीलिंग।

क्यों हुड्डा का पतन: एक किसान का कथन

करनाल के एक समृद्ध किसान ने माना कि फ़सलों का जो दाम मिला और बिजली की जैसी आपूर्ति हुड्डा सरकार के इस कार्यकाल में हुई, उसे अभूतपूर्व ही कहा जायेगा। साथ ही ज़मीन अधिग्रहण का इतना अधिक मुआवजा भी किसान को कभी नहीं मिला होगा। फ़िर भी, उसने कहा, हुड्डा को किसान वोट नहीं देंगे। क्यों? कदम-कदम पर भ्रष्टाचार और हर सरकारी नौकरी की नीलामी। कुशासन का यह आलम कि जरा सा काम कराने में धक्के ही धक्के!

'आप' : उलटेगी या सुलटेगी

'आप' का नेतृत्व फिलहाल 'उलटेगी' को स्वीकारने की मुद्रा में है। दिल्ली की सरकार को, बिना जनता को भरोसे में लिए, छोड़ना उनकी साख को किसी हद तक चोट पहुंचा गया। इसी तरह, अपने सीमित कार्यकर्ताओं के दम पर सारे देश में फैल जाने की रणनीति भी फ़लदायी सिद्ध नहीं हो रही।

सवाल है कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थिति को सुलटाने के लिए 'आप' क्या करे? सबसे पहले तो अपनी जिद - एक करोड़ सदस्य, 300 लोकसभा सीटें, 300 करोड़ चंदा - को तुरंत छोड़ दे। इसके साथ-साथ सारे देश में फैल अपने जैसी सोच वाले आन्दोलनों और व्यक्तियों की नेटवर्किंग कर पूरी शक्ति केन्द्रित करे। तीसरे, पार्टी का एक लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा करने पर ध्यान दे जिससे आसमान से टपकने वाले कृपापात्रों को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष न पनपे।

सबसे जरूरी है समाज की सांस्कृतिक रंगों में अपनी गतिविधियों को पहुंचाना क्योंकि चुनौति सरकारें हटाने की नहीं, वैकल्पिक राजनीति स्थापित करने की है। आरएसएस की हज़ारों शाखाओं, सैंकड़ों छात्र संगठनों और लाखों स्कूलों का मुकाबला करने के लिए जिस वैचारिक तैयारी की जरूरत है वह निरंतर चलने वाले सांस्कृतिक आन्दोलनों से ही संभव होगा। केवल क्रोनी-कैपिटल को गालियां देने से काम नहीं चलेगा, वैकल्पिक सोच के मंच भी बनाने होंगे।

सुलटना अब भी 'आप' के हाथ में ही है।

ख़बर दार

बी.जे.पी. का इलैक्शन मेनिफेस्टो उर्फ मोदीफेस्टो

खोदा पहाड़ निकली चुहिया– वो भी मरी हुई

यह वही पार्टी है जो मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताते नहीं थकती लेकिन अपने अध्यक्ष का गला दबाये हुये हैं। ना आडवाणी नजर आ रहे हैं ना सुषमा स्वराज । ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है ना दीन दयाल उपाध्याय को। बस मोदी-मोदी। कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई जवाब नहीं मांग सकता। यह वही मोदी है जो दो बार टी.वी.-पर बहस से भाग चुका है, जो किसी के सवालों के जवाब नहीं देता सिर्फ भाषण देता है, अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनता है और चलता बनता है।

बी.जे.पी. ने आखिर किसी तरह मर पड़ के अपना चुनाव घोषणापत्र (इलैक्शन मेनिफेस्टो) सोमवार, 7 अप्रैल को जारी कर दिया। क्योंकि मेनिफेस्टो जारी करने वाले दिन उत्तर पूर्व के राज्यों-असम, त्रिपुरा आदि में वोट पड़ने शुरू हो चुके थे, इससे ये लगता है कि या तो बी.जे.पी. इन राज्यों को भारत का हिस्सा नहीं मानती या फिर उसे इनकी वोटों की जरूरत ही नहीं। या फ़िर उसने सोचा होगा कि अब तक तो लोग़ समझ ही गये होंगे कि मोदी ही हमारा मेनिफेस्टो है इसलिये कोई मेनिफेस्टो जारी करो, ना करो या देर से करो क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो ये भी समझ से परे है कि इस मेनिफेस्टो को लिखने में ऐसी क्या अक्ल लगानी पड़ गई। जो बी.जे.पी. को इसे जारी करने में इतनी देर हो गई।

वैसे तो तीन मुद्दों-राम मन्दिर, धारा 370 और रिटेल में एफ.डी.आई, को छोड़ दें तो ये मेनिफेस्टो दसवी क्लास के बच्चे द्वारा लिखा निबन्ध सा प्रतीत होता है। ऐसा निबन्ध जो किसी किताब से टीप दिया गया हो, जिसमें ना कोई नवीनता है ना ही दृष्टिकोण की स्पष्टता। क्या ये वही बी.जे.पी. है जिसने पिछले कई महीने से आसमान सिर पर उठा रखा था कि वो देश की तस्वीर बदल देगी। वह गुजरात मॉडल सारे देश पर लागू करके उसे चार चांद लगा देगी। अरे भाई और कुछ नहीं तो गुजरात मॉडल को ही जरा विस्तार से समझा कर लिख देते कि उससे आप देश की आर्थिक उन्नत्ति कैसे सुनिश्चित करेंगे। ऊपर से तुर्रा यह कि पिछले एक महीने से मोदी जी एक नई आलाप ले रहे हैं कि- देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अरे भाई कम से कम अपने मेनिफेस्टो में ही बता देते कि देश को कौन मिटा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और आप कैसे देश को मिटने या बिकने से बचायेगें। या आपने इस देश को गधों और मूर्खों का तबेला समझ रखा है कि कोई बोलेगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं कि मोदी नाम का एक अवतार अब आ चुका है जो सारे कष्टों, दुखों को दूर कर देगा बस आप श्रद्धा से उसके आगे शीश नवाओ।

मेनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल, पर्यावरण सुरक्षा, श्रमिकों और किसानों की दशा सुधारने, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अदि विषयों पर हल्की-फुल्की सी कुछ लाइनें लिखकर छुट्टी पा ली गई है।

शेष पेज 2 पर